

इज़राइल द्वारा फ़िलिस्तीनियों का अमानवीकरण: एक व्यवस्थित क्रूरता जो पशुओं के साथ व्यवहार से भी बदतर है

इज़राइल की फ़िलिस्तीनियों को अमानवीय बनाने की मुहिम उनके अस्तित्व पर एक सुनियोजित और निर्मम हमला है, जो उन्हें पशुओं से भी निम्न स्तर पर लाकर नियंत्रित, शोषित और मिटाने योग्य वस्तुओं के रूप में व्यवहार करता है। नरसंहारक बयानबाजी, कठोर प्रशासनिक हिरासत, यातनापूर्ण जेल की स्थिति, गाजा में सामूहिक नरसंहार, बिना सहमति के चिकित्सीय प्रक्रियाएँ, ऐतिहासिक रूप से पुष्ट अंग निकालना, और इन अपराधों को छिपाने के लिए शवों को जानबूझकर रखना या सामूहिक कब्रों में दफनाना, इन सभी के माध्यम से इज़राइल ने भयावह सटीकता के साथ फ़िलिस्तीनियों की मानवता छीन ली है। शवों को तब तक रखना जब तक वे सड़कर ऑटोप्सी के लिए अनुपयोगी न हो जाएँ, या उन्हें बिना निशान वाली सामूहिक कब्रों में दफनाना, केवल लापरवाही नहीं है, बल्कि एक घृणित प्रयास है जिसका उद्देश्य अत्याचारों के साक्ष्य मिटाना और इज़राइल को जवाबदेही से बचाना है। यह लेख दृढ़ विश्वास के साथ तर्क देता है कि ये प्रथाएँ नैतिक और कानूनी रूप से घृणित हैं, जो फ़िलिस्तीनियों को मिटाने के दशकों पुराने प्रोजेक्ट में निहित हैं, और वैश्विक निंदा व न्याय की माँग करती हैं।

नरसंहारक बयानबाजी: अमानवीकरण का आधार

इज़राइल द्वारा फ़िलिस्तीनियों का अमानवीकरण उन शब्दों से शुरू होता है जो सामूहिक चेतना को विषाक्त करते हैं, फ़िलिस्तीनियों को ऐसी निम्न मानव इकाइयों में बदल देते हैं जो जीवन या सम्मान के हकदार नहीं हैं। अपनी स्थापना से ही नेताओं ने फ़िलिस्तीनी अस्तित्व को नकारने के लिए भाषा का उपयोग किया है। गोल्डा मेयर का 1969 का कुख्यात बयान, “कोई फ़िलिस्तीनी जैसी चीज़ नहीं थी... वे मौजूद नहीं थे,” ने उनकी पहचान और इतिहास को मिटाकर उन्हें गैर-मौजूद इकाइयों की तरह व्यवहार करने वाली नीतियों के लिए आधार तैयार किया (नरसंहार की भाषा)। यह बयानबाजी समकालीन नेताओं में भी जारी है, जो हिंसा को 正当 करने के लिए अमानवीकरण को बढ़ावा देते हैं। अक्टूबर 2023 के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषणों ने फ़िलिस्तीनियों को बाइबिल के अमालेकियों से तुलना की, जिनके पूर्ण विनाश की ईश्वरीय आज्ञा थी, और उन्हें “अंधेरे के बच्चे” करार दिया, जिससे उन्हें नष्ट करने योग्य अस्तित्वगत खतरे के रूप में चित्रित किया गया (फ़िलिस्तीनियों का अमानवीकरण)। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का भयावह दावा, “हम मानव पशुओं से लड़ रहे हैं और हम उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं,” गाजा में भोजन, पानी और बिजली काटने वाले घरे के साथ था, जिसने फ़िलिस्तीनियों को स्पष्ट रूप से उन राक्षसों के रूप में चित्रित किया जो भुखमरी के हकदार हैं (इज़राइल में फ़िलिस्तीनियों को अमानवीय बनाने वाली बयानबाजी)। वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच की शिकायत कि दुनिया “इज़राइल को 20 लाख नागरिकों को भुखमरी से मरने की अनुमति नहीं देगी,” सामूहिक मृत्यु को समाधान के रूप में सामान्य करने वाली नरसंहारक मंशा को उजागर करती है (इज़राइली समाज का अमानवीकरण)। यह भाषा नागरिक समाज में भी व्याप्त है, जहाँ मीडिया हस्तियाँ जैसे येहुदा श्लेज़िंगर फ़िलिस्तीनी कैदियों के साथ बलात्कार की वकालत करते हैं, और नेसेट के सदस्य सैनिकों को यौन हिंसा सहित असीमित कार्रवाई की अनुमति देने की माँग करते हैं (इज़राइली समाज का अमानवीकरण)। यह बयानबाजी केवल अतिशयोक्ति नहीं है; यह अत्याचारों का जानबूझकर किया गया प्रस्तावना है, जो एक ऐसी संस्कृति को जन्म देती है जहाँ फ़िलिस्तीनियों की पीड़ा का उत्सव मनाया जाता है, और उनके जीवन उन पशुओं से भी कम मूल्यवान समझे जाते हैं जो इस तरह की घृणा से बचे रहते हैं।

प्रशासनिक हिरासत: एक काफ़काई रसातल

इज़राइल की प्रशासनिक हिरासत की प्रथा एक भयावह नियंत्रण तंत्र है, जो फ़िलिस्तीनियों को—प्रायः नाबालिगों को—बिना किसी आरोप, मुकदमे या स्पष्टीकरण के कैद करती है, एक कानूनी शून्य में जो मानव गरिमा को चुनौती देता है। 9,400 से अधिक फ़िलिस्तीनी, जिनमें सैकड़ों बच्चे शामिल हैं, हिरासत में पीड़ित हैं; नवंबर 2023 तक 3,242 से अधिक प्रशासनिक रूप से हिरासत में हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार (संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट)। कैदियों को बिना संपर्क के

रखा जाता है, गैरकानूनी युद्धक कानून के तहत 140 दिनों तक वकीलों या परिवारों से संपर्क करने से वंचित किया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) की मुलाकातों से रोक दिया जाता है, जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय नियम (ICCPR) और बाल अधिकार संधि (CRC) का उल्लंघन करता है (एमनेस्टी इंटरनेशनल)। यह गोपनीयता, जिसमें परिवार अपने प्रियजनों की स्थिति से अनजान रहते हैं, उपयोगिता के लिए वस्तुओं की तरह व्यवहार को दर्शाती है, न कि संवेदनशील प्राणियों को। 2024 में विस्तारित कानून बिना न्यायिक निरीक्षण के हिरासत की अनुमति देता है, जिससे फ़िलिस्तीनी चुप और अदृश्य हो जाते हैं। नाबालिग, जैसे एक 14 वर्षीय बच्चा जो 24 दिनों तक हिरासत में रहा और यातना झेली, विशेष भय का सामना करते हैं, उनकी युवावस्था को एक ऐसे तंत्र द्वारा अनदेखा किया जाता है जो उन्हें अनिश्चितकाल के लिए कैद करने योग्य खतरों के रूप में देखता है (एमनेस्टी इंटरनेशनल)। पशु, जो अपनी उपयोगिता के लिए बुनियादी देखभाल प्राप्त करते हैं, के विपरीत, फ़िलिस्तीनियों को जानबूझकर व्यक्तित्व मिटाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उनकी सत्ता को एक नौकरशाही फुटनोट तक सीमित कर दिया जाता है।

यातनापूर्ण हिरासत की स्थिति: नरक में उतरना

इज़राइल के हिरासत केंद्रों में स्थितियाँ फ़िलिस्तीनियों के अमानवीकरण का प्रमाण हैं, जो कैदियों को यातना, बलात्कार और उपेक्षा के दुःस्वप्न भरे रसातल में धकेलती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी'त्सेलेम, और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें एक भयावह चित्र प्रस्तुत करती हैं: कैदी पिंजरे जैसे बाड़ों में रखे जाते हैं, उनकी आँखों पर पट्टी बाँधी जाती है, हथकड़ी लगाई जाती है, और उन्हें डायपर पहनने के लिए मजबूर किया जाता है; भोजन, पानी, बिस्तर और चिकित्सा देखभाल से वंचित रखा जाता है (बी'त्सेलेम)। यातना व्यवस्थित है—पिटार्ई, बिजली के झटके, वाटरबोर्डिंग, छत से लटकाना, और कुत्तों के हमले दर्ज किए गए हैं, अक्टूबर 2023 के बाद से हिरासत में कम से कम 54 मौतें हुई हैं (संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट)। यौन हिंसा व्यापक है; सामूहिक बलात्कार, अग्निशामक नोजल जैसे वस्तुओं से बलात्कार, और कुत्तों द्वारा बलात्कार के दावे, विशेष रूप से स्टे इमान में, संयुक्त राष्ट्र और द न्यू अरब की रिपोर्टों के अनुसार दर्ज किए गए हैं (द न्यू अरब)। महिलाएँ और बच्चे विशेष भय का सामना करते हैं, उन्हें सैनिकी पैड से वंचित रखा जाता है और नग्न तलाशी के अधीन किया जाता है; एक नर्स ने संयुक्त राष्ट्र की सुनवाई में बलात्कार के कारण रक्तस्राव की गवाही दी (आरएफआई)। बी'त्सेलेम का इन सुविधाओं को “यातना शिविर” कहना उनकी क्रूरता को रेखांकित करता है; यह पशुओं की उपेक्षा से भी आगे जाता है, क्योंकि पशुओं को कम से कम उनकी कीमत बनाए रखने के लिए भोजन और आश्रय दिया जाता है। इसके विपरीत, फ़िलिस्तीनियों को जानबूझकर पीड़ा दी जाती है, उनके शरीर और आत्मा को उनकी निम्न मानव स्थिति को पुष्ट करने के लिए तोड़ा जाता है, एक ऐसा भाग्य जो किसी भी पशु को इतनी सुनियोजित क्रूरता के साथ नहीं झेलना पड़ता।

गाजा में सामूहिक नरसंहार: एक उजागर नरसंहार

गाजा में फ़िलिस्तीनियों का सामूहिक नरसंहार, विशेष रूप से अक्टूबर 2023 के बाद से, अमानवीकरण का एक भयावह चरम है; एमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र ने इसे संभावित नरसंहार के रूप में वर्णित किया है, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएँ और बच्चे शामिल हैं, 53,000 से अधिक लोग मारे गए हैं (एमनेस्टी इंटरनेशनल)। इज़राइल के अंधाधुंध हवाई हमले, जो अस्पतालों, स्कूलों और शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाते हैं, फ़िलिस्तीनी जीवन के प्रति क्रूर उदासीनता को दर्शाते हैं, जिसे उन्हें “मानव पशु” के रूप में चित्रित करने वाली बयानबाजी द्वारा उचित ठहराया जाता है। भोजन, पानी और दवाइयों को काटने वाला घेरा भुखमरी और बीमारी का कारण बना; स्मोट्रिच की टिप्पणियाँ इसे एक स्वीकार्य परिणाम के रूप में सुझाती हैं (इज़राइली समाज का अमानवीकरण)। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार गाजा के 70% आवास और बुनियादी ढाँचे का विनाश क्षेत्र को निर्जन बनाने का लक्ष्य रखता है, जो जेनेवा संधियों के सामूहिक दंड के निषेध का स्पष्ट उल्लंघन है (संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट)। विशेष क्रूरताएँ, जैसे अल-अहली बैपटिस्ट अस्पताल पर हवाई हमला, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हिंसा के पैमाने को रेखांकित करते हैं (फ़िलिस्तीनियों का अमानवीकरण)। यह युद्ध नहीं है; यह उन्मूलन है, जो फ़िलिस्तीनियों को नष्ट करने योग्य कीटों के रूप में मानता है, जो पशुओं से भी बदतर है, जिन्हें इस तरह के लापरवाह विनाश से बचाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने जनवरी 2024 में इज़राइल को नरसंहार रोकने का आदेश दिया, लेकिन नरसंहार, फ़िलिस्तीनी मृत्यु को सामान्य करने वाली अमानवीकरण बयानबाजी से प्रेरित होकर, जारी है (ICJ निर्णय)।

बिना सहमति की चिकित्सीय प्रक्रियाएँ: शारीरिक पवित्रता का उल्लंघन

इज़राइल के बिना सहमति या एनेस्थेसिया के प्रक्रियाएँ करने के आरोप फ़िलिस्तीनी शारीरिक अखंडता के खिलाफ एक घृणित उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके शरीर को शोषण के लिए वस्तुओं के रूप में मानते हैं। स्टे तेइमान में हथकड़ी की चोटों से होने वाली “नियमित” विच्छेदन, जो घृणित परिस्थितियों में किए गए, चिकित्सीय लापरवाही या जानबूझकर नुकसान का संकेत देते हैं, अप्रैल 2024 की सीएनएन रिपोर्ट के अनुसार (सीएनएन रिपोर्ट)। ऐसी प्रक्रियाएँ, यदि बिना सहमति या एनेस्थेसिया के की जाती हैं, ICCPR के बिना सहमति के चिकित्सीय कृत्यों के निषेध और यातना विरोधी संधि (CAT) का उल्लंघन करती हैं, जो यातना या अमानवीय व्यवहार का गठन करती हैं। हिरासत सुविधाओं में पारदर्शिता और चिकित्सा रिकॉर्ड तक पहुँच की कमी दुर्व्यवहार के संदेह को बढ़ाती है। पशु, जो अपनी उपयोगिता के लिए विनियमित चिकित्सा उपचार प्राप्त करते हैं, के विपरीत, फ़िलिस्तीनियों को उन प्रक्रियाओं के अधीन किया जाता है जो उनकी गरिमा और स्वायत्तता को अनदेखा करती हैं, जिससे उनकी अमानवीय स्थिति को और सुदृढ़ किया जाता है, जो केवल दंड या प्रयोग के लिए बर्तन हैं।

ऐतिहासिक अंग निकालना और शवों को रखकर अपराधों को छिपाना

इज़राइल का ऐतिहासिक अंग निकालने का स्वीकार और वर्तमान में फ़िलिस्तीनी शवों को तब तक रखना जब तक वे ऑटोप्सी के लिए अनुपयोगी न हो जाएँ या उन्हें सामूहिक कब्रों में दफनाना, इसके घृणित अपराधों को छिपाने के इरादे का एक विनाशकारी आरोप है। 2009 में, अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रमुख डॉ. येहुदा हिस ने स्वीकार किया कि 1990 के दशक में पैथोलॉजिस्टों ने परिवार की अनुमति के बिना फ़िलिस्तीनियों, इज़राइलियों और विदेशी श्रमिकों से कॉर्निया, त्वचा, हृदय वाल्व और हड्डियाँ निकाली थीं, जैसा कि द गार्जियन ने बताया (द गार्जियन)। इस स्वीकारोक्ति ने पुष्टि की कि फ़िलिस्तीनी शवों का शोषण किया गया, उनकी पवित्रता को निर्जन वस्तुओं से संसाधन निकालने की तरह उल्लंघन किया गया। यूरो-मेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर (2023) के हालिया दावों में कहा गया है कि गाजा से लौटाए गए शवों में लीवर और किडनी जैसे अंग गायब हैं, हालाँकि संघर्ष और सड़न के कारण फॉरेंसिक साक्ष्य बाधित हैं (यूरो-मेड मॉनिटर)। जदालिया के अनुसार 370 से अधिक शवों को रखा जाना, जिनमें से 115 से अधिक मोर्ग में और 256 “नंबरर्स कब्रिस्तान” के रूप में जाना जाने वाला नंबर वाली कब्रों में हैं, एक ऐसी सुनियोजित रणनीति है जो इस तरह के दुरुपयोग को उजागर करने वाली ऑटोप्सी को रोकती है (जदालिया)। 5 अगस्त 2024 को गाजा को 89 सड़े हुए शवों की वापसी, जो अल जज़ीरा के अनुसार नासर अस्पताल के पास बिना पहचान के सामूहिक कब्र में दफनाए गए, और 25 सितंबर 2024 को 88 शवों को उनकी अपरिचित स्थिति के कारण स्वीकार करने से इनकार, मिडिल ईस्ट आई के अनुसार, साक्ष्य मिटाने का जानबूझकर किया गया प्रयास सुझाता है (अल जज़ीरा, मिडिल ईस्ट आई)। पशुओं के अवशेषों, जो नियामक निरीक्षण के साथ संभाले जाते हैं, के विपरीत, फ़िलिस्तीनी शवों को उनकी व्यक्तिगतता को मिटाने और संभावित अपराधों को छिपाने के तरीके से रखा या फेंका जाता है, एक ऐसी प्रथा जो अपराधबोध और दंडमुक्ति की चीख पुकार करती है।

कानूनी निहितार्थ: अंतरराष्ट्रीय कानून पर बेशर्म हमला

इज़राइल के कार्य अंतरराष्ट्रीय कानून पर एक बेशर्म हमला हैं, जो कई ढांचों का बिना सजा के उल्लंघन करते हैं: - **संयुक्त राष्ट्र चार्टर**: अनुच्छेद 1 का मानवाधिकारों का आह्वान फ़िलिस्तीनी गरिमा को नकारने वाली अमानवीकरण नीतियों द्वारा खारिज किया जाता है (संयुक्त राष्ट्र चार्टर)। - **ICCPR और CAT**: मनमानी हिरासत, यातना, और बिना सहमति की चिकित्सीय कृत्य अनुच्छेद 7 और 9 का उल्लंघन करते हैं, अंग निकालना यातना और अंग-विच्छेदन का गठन करता है (ICCPR, CAT)। - **जेनेवा संधियाँ**: चौथी संधि यातना, सामूहिक दंड, और मृतकों के प्रति अनादर को निषिद्ध करती है, जो गाजा में, हिरासत प्रथाओं में, और शवों को रखने में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है (जेनेवा संधियाँ)। - **रोम संधि**: अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) द्वारा नवंबर 2024 में नेतन्याहू और गैलेंट के लिए हत्या, यातना और भुखमरी सहित युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट व्यक्तिगत जवाबदेही को रेखांकित करते हैं (ICC मामले)। - **ICJ निर्णय (जुलाई 2024)**: इज़राइल के कब्जे को अवैध घोषित किया, जिसमें मनमानी हिरासत और सामूहिक दंड सहित व्यवस्थित उल्लंघनों का उल्लेख किया गया (ICJ निर्णय)। - **संरक्षण की जिम्मेदारी (R2P)**: कथित नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध वैश्विक हस्तक्षेप की जिम्मेदारियों को ट्रिगर करते हैं, लेकिन राजनीतिक गठजोड़ कार्रवाई को रोकते हैं (R2P)। - **प्रथागत अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून**: अनावश्यक पीड़ा को निषिद्ध करता है और मृतकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार का आदेश देता है, दोनों ही इज़राइल की प्रथाओं द्वारा उल्लंघन किए जाते हैं (प्रथागत IHL)।

शवों को ऑटोप्सी रोकने के लिए रखना चौथी जेनेवा संधि के अनुच्छेद 16 का सीधा उल्लंघन है, जो सम्मानजनक दफन की आवश्यकता को निर्धारित करता है, और प्रथागत अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के सम्मानजनक निपटान के आदेश का। ये

कार्य युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, और संभावित नरसंहार का गठन करते हैं, जिनके लिए अभियोजन, प्रतिबंध, और अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

नैतिक रसातल: पशुओं से भी बदतर

पशु, जिन्हें उनकी आर्थिक उपयोगिता के लिए मूल्यवान माना जाता है, उन्हें भोजन दिया जाता है, आश्रय दिया जाता है, और उनकी कीमत बनाए रखने के लिए नियंत्रित किया जाता है। इसके विपरीत, फ़िलिस्तीनियों को एक जानबूझकर किए गए उन्मूलन अभियान के अधीन किया जाता है— उन्हें भुखमरी, यातना, नरसंहार, और शोषण का सामना करना पड़ता है, उनके शवों को अपराधों को छिपाने के लिए रखा या फेंका जाता है। अंग निकालने का ऐतिहासिक स्वीकार और शवों को सड़ने तक रखने की वर्तमान प्रथा जवाबदेही से बचने की भयावह मंशा को उजागर करती है, फ़िलिस्तीनी अवशेषों को सम्मान के हकदार मानव जीवन के बजाय मिटाने योग्य साक्ष्य के रूप में मानते हैं। यह केवल एक चूक नहीं है; यह एक व्यवस्थित प्रयास है जो फ़िलिस्तीनियों को भुला देने तक अमानवीय बनाता है, उनकी पीड़ा को अदृश्य और उनकी मृत्यु को तुच्छ बनाता है।

निष्कर्ष: न्याय की माँग

इज़राइल द्वारा फ़िलिस्तीनियों का अमानवीकरण—नरसंहारक बयानबाजी, प्रशासनिक हिरासत, यातनापूर्ण स्थिति, सामूहिक नरसंहार, चिकित्सीय दुरुपयोग, ऐतिहासिक अंग निकालना, और शवों को रखकर या सामूहिक कब्रों में दफनाकर अपराधों को जानबूझकर छिपाने के माध्यम से—एक नैतिक और कानूनी घृणा है। यह एक पूरे लोगों को पशुओं से भी निम्न स्तर पर ले जाता है, सुनियोजित क्रूरता के साथ व्यवहार करता है जो मानवता के नैतिक आधारों को चुनौती देता है। वैश्विक समुदाय को निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए: व्यापक प्रतिबंध लागू करना, ICC और ICJ की जाँचों का समर्थन करना, R2P को लागू करना, और उचित दफन के लिए रखे गए शवों की तत्काल रिहाई की माँग करना। इसे अनदेखा करना एक नैतिक रसातल को सहन करना है जहाँ एक पूरा लोग मिटा दिया जाता है, उनकी पीड़ा को पार्श्विक क्षति के रूप में खारिज किया जाता है। दुनिया को इज़राइल की क्रूरताओं का सामना उसी तात्कालिकता के साथ करना चाहिए जो वह किसी अन्य नरसंहार के लिए माँग करेगा, और उन फ़िलिस्तीनियों के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए जिनकी मानवता को इतनी क्रूरता से नकारा गया है।

प्रमुख स्रोत

- फ़िलिस्तीनियों का अमानवीकरण
- एमनेस्टी इंटरनेशनल
- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट
- बी'त्सेलेम
- अल जज़ीरा
- मिडिल ईस्ट आई
- जदालिया
- द गार्जियन
- यूरो-मेड मॉनिटर
- सीएनएन रिपोर्ट
- ICJ निर्णय
- ICC मामले
- द न्यू अरब
- आरएफआई